[Social Issues and Environmental Problems,Vol.3 (Iss.9:SE): Sep, 2015] ISSN- 2350-0530(O) ISSN- 2394-3629(P)
Impact Factor: 2.035 (I2OR)
DOI: https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v3.i9SE.2015.3224

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH
A knowledge Repository

कार्बन ट्रेडिंग एंव कार्बन क्रेडिट जलवायु परिवर्तन समस्या समाधान में सहायक

दिवाकर सिंह तोमर
श्री नटनागर शोध संस्थान, सीतामऊ, मंदसौर (म.प्र.)

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन सबसे ज्वलंत पर्यावरणीय समस्या बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाऊस गैसें है। ग्रीन हाऊस गैसों के अन्तर्गत कार्बनडाई आक्साइड, मिथेन, नाइट्रस आक्साइड, ओजोन जैसी गैसें आती हैं। इसमें कार्बनडाईआक्साइड सबसे खतरनाक है। जो देश जितना ज्यादा विकसित है कार्बन उत्सर्जन में उसकी भागीदारी उतनी ही ज्यादा है।
वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र होने के बाबजूद प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत शीर्ष तीन कार्बन उत्सर्जन राष्ट्रों से काफी पीछे है। ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन करने वाली शीर्ष 05 राष्ट्र

राष्ट्र	कुल उत्सर्जन प्रतिशत में
चीन	25.26
यूएस	14.4
यूरोपीय संघ	10.16
भारत	6.96
रूस	5.36

जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए न तो विकसित देश और न ही विकासशील देश जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। क्योंकि कोई विकास से समझौता नहीं करना चाहता है। इसी कारण यह समस्या ओर घातक बनती जा रही है। अभी हाल ही में ग्रीन हाऊस गैसों के कारण विश्व के समक्ष समस्याएँ उभकर सामने आई हैं।

1) ओजोन परत में छिद्र :– धरती के वातावरण में मौजूद ओजोन की परत हमें सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं। परन्तु हवाई ईधन और रेफ्रिजरेशन उद्योग से उत्सर्जित होने वाली क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस से धरती के वातावरण में विद्यमान ओजोन की सुरक्षा छतरी में छिद्र हो गए हैं।

2) समुद्र स्तर में वृद्वि :– वैश्विक तपन के फलस्वरूप हिम पिघल रहे हैं जिसके कारण समुद्र के जल स्तर में तेजी से वृद्वि हो रही है।

3) भूजल का विशैला होना :– समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटवर्ती क्षेत्रों के भूजल के खारा होने का खतरा बढ़ गया है।

4) ध्रवों की बर्फ का पिघलना :– वैश्विक तपन के कारण पृथ्वी के ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। इससे समुद्र के जल स्तर में वृद्वि हो रही है।

5) वन क्षेत्रों का सिकुड़ना :– बदलते मौसम औद्योगीकरण और शहरीकरण जंगलों की कटाई से वन क्षेत्र काफी सीमित होता जा रहा है।

6) लुप्त प्राय जीव :– उपर्युक्त समस्याओं के कारण धरती पर जैवविविधता संकीर्ण होती जा रही है। अंदेशा है कि वैश्विक तपन के दुष्प्रभाव से धरती पर विद्यमान पौधों की 56 हजार प्रजातियों और जीवों की 37000 नस्लें लुप्त प्राय होती जा रही हैं।

इन्ही समस्याओं को देखते हुए डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दिसम्बर के मध्य में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बाद समूचे विश्व में जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में बहस तेज हो गई है। इसके पहले जलवायु परिवर्तन समस्या समाधान में जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए उनमें 1997 में जापान के क्योटो में हुए सम्मेलन में 40 औद्योगिक देशों के लिए 1990 के स्तर के आधार पर ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन के मानक तय किये हुए तत्पश्चात् दिसम्बर 2004 में कार्बन व्यवसाय को लेकर डरबन सम्मेलन तथा फरवरी 2005 में पुनः क्योटो प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देते हुए 2012 तक 1990 के स्तर पर कार्बनडाईऑक्साईड उत्सर्जन लाने को सहमति हुई। इसी संदर्भ में 2007 में बाली में हुए सम्मेलन में विकसित देशों पर जिम्मेदारी डाली गई क्योंकि मात्र 20 प्रतिशत संख्या वाले ये देश 80 प्रतिशत कार्बनडाईऑक्साईड का उत्सर्जन करते हैं।

कार्बन ट्रेडिंग

सरल शब्दों में ऐसे विकसित देश जो अपने हिस्से का कार्बन उत्सर्जन कर चुके हैं किन्तु विकास करना चाहते हैं और विकास से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते हैं। वे ऐसे विकासशील देशों जिनके पास बहुत बड़ा कार्बन बाजार है से कार्बन खरीद सकते है और बदले में विकासशील देशों को पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना होगी जिससे ये देश भी अपने विकास कार्य को बढ़ावा दे सकें तथा विकासशील देशों में वृक्षारोपण कराना होगा जिससे विकासशील देशों में ग्रीन हाऊस गैसों की मात्रा में वृद्वि न हो।

कार्बन क्रेडिट

स्वच्छ विकास तंत्र (क्लीन डेवलमेंट मैकेनिज्म) विकसित देशों में सरकारों या कम्पनियों को विकासशील देशों में किए गए स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश पर ऋण अर्जित करने की अनुमति देता है। इस ऋण को ही कार्बन क्रेडिट्स कहा जाता है। कार्बन क्रेडिट को कार्बन यूनिट में मापा जाता है। एक कार्बन यूनिट एक टन कार्बन के बराबर है। कार्बन क्रेडिट्स अर्जित करने की पात्र सौर, पवन या जल बिजली जैसी अक्षय ऊर्जा वेंचर परियोजनाएँ होती है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क संधि की पहल पर हुए इस सर्वे के अनुसार विश्व के 78.53 प्रतिशत लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर बेहद चिंतित है जबकि भारत में यह ऑकड़ा 83.65 प्रतिशत है।

भारत की स्थिति

भारत का मानना है कि वायुमंडल में ग्रीन हाऊस गैसों का जो भंडार है वह पिछले 150–200 वर्षो में जमा हुई है और इसके लिए एनेक्स–1 के देश ही उत्तरदायी हैं अतः उत्सर्जन में कटौती भी इन्ही को करना चाहिए।

सन्दर्भ

1. *योजना मासिक पत्रिका – जनवरी, 2010 ISSN 7 0971–8393*
2. *भूगोल और आप – जुलाई, सितम्बर, 2010*
3. *सिविल सर्विसेस क्रॉनिकल – अगस्त, 2012*
4. *योजना – जून, 2013*
5. *आई.सी.एल.ई.आई. रिपोर्ट – 2014*
6. *यू.एन.एफ.सी.सी. रिपोर्ट – 2015*
7. *आई.पी.सी.सी. रिपोर्ट – 2015*
8. *यूरोपीय पर्यायवरण एजेंसी ऑफीशियल वेब*
9. *यू.एन.एनवायरमेंट प्रोग्राम ऑफीशियल वेब*
10. *दि एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफीशियल वेब*
11. *वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यट रिपोर्ट ऑफीशियल वेब*